

इंफोमेटिक्स

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित एवं ई गवर्नेंस बुलेटिन

संपादकीय संयोजन : प्रिस्का लाकड़ा



श्रृंखला, एक ब्लॉकचेन-सक्षम शैक्षणिक प्रमाणन प्रणाली, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई

शिक्षा क्षेत्र के डिजिटलीकरण में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश भगेल ने अभूतपूर्व ब्लॉकचेन-सक्षम अकादमिक प्रमाणन परियोजना, “श्रृंखला” लॉन्च की। परियोजना का उद्देश्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता का लाभ उठाते हुए, अकादमिक प्रमाणपत्रों को संग्रहीत और साझा करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह लॉन्च शनिवार, 22 अप्रैल 2023 को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और डिग्रियों को कागज पर संग्रहीत करने की पारंपरिक पद्धति लंबे समय से एक बोझिल और कमजोर प्रक्रिया रही है। इससे अक्सर नकली प्रमाणपत्र, सत्यापन में देरी और अकादमिक रिकॉर्ड तक पहुंचने में कठिनाई जैसे मुद्दे सामने आते हैं। श्रृंखला का कार्यान्वयन अकादमिक प्रमाणपत्रों के लिए एक सुरक्षित और छेड़छाड़-प्रूफ प्रणाली शुरू करके इन चुनौतियों का समाधान करना चाहता है।

ब्लॉकचेन तकनीक, जो अपनी विकेंद्रीकृत और पारदर्शी प्रकृति के लिए जानी जाती है, अकादमिक प्रमाणपत्रों के डिजिटल परिवर्तन के लिए एक आदर्श समाधान प्रदान करती है। ब्लॉकचेन का लाभ उठाकर, श्रृंखला यह सुनिश्चित करती है कि अकादमिक रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहीत और आसानी से सत्यापित किए जा सकें। ब्लॉकचेन की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता यह सुनिश्चित करती है कि एक बार प्रमाणीकरण दर्ज हो जाने के बाद, इसे बदला या छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है।

श्रृंखला व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं को शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित करने की अनुमति देता है। बस कुछ ही क्लिक के साथ, उपयोगकर्ता ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली तक पहुंच सकते हैं और प्रमाणीकरण के विवरण को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे मैन्युअल सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है जो अक्सर समय लेने वाली होती हैं।

ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाकर, छत्तीसगढ़ अपने शिक्षा क्षेत्र की दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नवीन समाधानों का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। श्रृंखला की शुरुआत भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि के



छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेश भगेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में ब्लॉकचेन-सक्षम शैक्षणिक प्रमाणन परियोजना “श्रृंखला” का शुभारंभ किया

अनुरूप है, जहां प्रगति और समावेशिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में श्रृंखला का सफल कार्यान्वयन देश भर के अन्य राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, डेटा भंडारण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी ढांचा प्रदान करता है।

ब्लॉकचेन तकनीक के साथ अकादमिक प्रमाणपत्रों के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ, हम एक अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली की आशा कर सकते हैं जिससे छात्रों, नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को समान रूप से लाभ होगा। जैसा कि अन्य राज्य और संगठन ब्लॉकचेन की क्षमता को पहचानते हैं, हम इसी तरह की परियोजनाओं को व्यापक रूप से अपनाने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे भारत और उसके बाहर शिक्षा के परिदृश्य में बदलाव आएगा।

- वाई वी श्रीनिवास राव, छत्तीसगढ़

गोवा के माननीय मुख्यमंत्री ने एआई-आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया

27 मार्च 2023 को, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने गोवा में मर्सिस जंक्शन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली सुरक्षा और कुशल सिग्नल प्रबंधन सुनिश्चित करने में राज्य अधिकारियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। एआई तकनीक का उपयोग करके, सिस्टम स्वचालित रूप से उल्लंघन की पहचान करता है और उल्लंघनकर्ता के पते पर तुरंत ई-चालान भेजता है।

इस प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करना और यातायात प्रबंधन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में साक्ष्य के रूप में वास्तविक समय की तस्वीरें ली जाएंगी, जिससे सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होगा। उल्लेखनीय है कि यह प्रणाली भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही चालू है।

सिस्टम में उन्नत क्षमताएं हैं, जिसमें विभिन्न उल्लंघनों का पता लगाने की क्षमता शामिल है, जैसे गति सीमा से अधिक होना, लाल बत्ती चलाना, स्टॉप लेन का उल्लंघन, बिना हेलमेट के सवारी करना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, ट्रिपल-राइडिंग और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना।

यातायात उल्लंघनों की पहचान करने की प्रक्रिया स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) प्रणाली से शुरू होती है, जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उल्लंघनों को पकड़ लेती है। इसके बाद सिस्टम वाहन और सारथी डेटाबेस से वाहन और लाइसेंस विवरण प्राप्त करता है। उल्लंघन की पहचान होने पर, एक नोटिस तैयार किया जाता है और उल्लंघनकर्ता को भेजा जाता है। उल्लंघनकर्ता ई-चालान प्रणाली के माध्यम से आसानी से चालान राशि का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।



गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद सावंत, गोवा में मर्सिस जंक्शन पर आईटीएमएस का शुभारंभ करते हुए

कुल मिलाकर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) का कार्यान्वयन ट्रैफिक पुलिस को प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। एकत्रित डेटा को ट्रैफिक पुलिस के स्वामित्व वाले सर्वर पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाता है, जिससे ट्रैफिक पैटर्न का व्यापक विश्लेषण और निगरानी संभव हो पाती है। इसके अलावा, पुलिस बल की भविष्य में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ट्रैक करने और चोरी हुए वाहनों की पहचान करने के लिए इस प्रणाली का लाभ उठाने की योजना है, जिससे सड़कों पर सुरक्षा उपायों को और बढ़ाया जा सके।

- अर्चना नागवेकर, गोवा

सार्वजनिक खरीद में बढ़ती जरूरतों को संबोधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खरीद पर राष्ट्रीय सम्मेलन

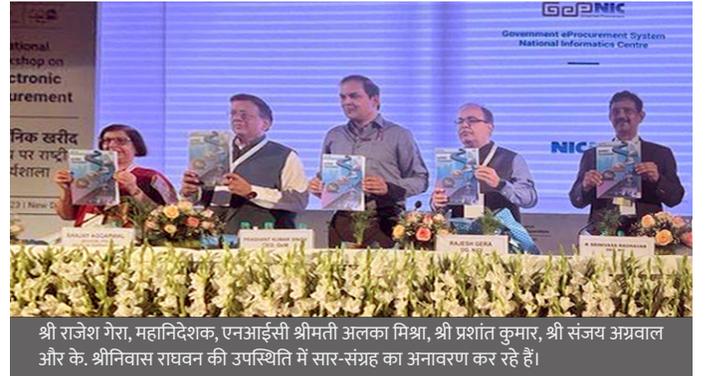
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीआई) के सहयोग से 27 मार्च 2023 को प्रतिष्ठित इंडिया हैबिटेट सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक खरीद पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में उभरती जरूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करना, इलेक्ट्रॉनिक खरीद के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और निष्पक्षता, दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में जीईएम, रेलवे और जीईपीएनआईसी जैसे प्रमुख सार्वजनिक खरीद पोर्टलों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग एक साथ आए।

उद्घाटन सत्र में एनआईसी के महानिदेशक श्री राजेश गेरा और जीईएम के सीईओ श्री प्रशांत कुमार सहित प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति देखी गई। श्री राजेश गेरा ने ई-प्रोक्वोरमेंट प्रणाली और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार में ई-प्रोक्वोरमेंट प्रणाली द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया।

श्री प्रशांत कुमार ने अपने संबोधन में जीईएम में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, इसकी प्रमुख विशेषताओं और नई कार्यक्षमताओं के समावेश पर प्रकाश डाला। जीईएम ने भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति ला दी है, जो सरकारी संगठनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को सहजता से खरीदने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य कर रहा है। सीईओ के भाषण ने जीईएम को बढ़ाने और इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में खरीद नीति प्रभाग (पीपीडी) के सलाहकार श्री संजय अग्रवाल ने ई-खरीद प्रणाली की कार्यविधि और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की। उनके संबोधन में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक खरीद में हुई उल्लेखनीय प्रगति को उजागर किया और इसकी दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण आकर्षण एनआईसी के महानिदेशक श्री राजेश गेरा द्वारा जी ई पी एन आई सी सार-संग्रह का विमोचन था। यह सार-संग्रह सरकारी ई-प्रोक्वोरमेंट प्रणाली की कार्यविधि को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, जो भारत में सार्वजनिक खरीद पर इसके विकास,



श्री राजेश गेरा, महानिदेशक, एनआईसी श्रीमती अलका मिश्रा, श्री प्रशांत कुमार, श्री संजय अग्रवाल और के. श्रीनिवास राघवन की उपस्थिति में सार-संग्रह का अनावरण कर रहे हैं।

उपलब्धियों और प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह उन संगठनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है जो असाधारण परिणामों के लिए ई-प्रोक्वोरमेंट प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक खरीद पर राष्ट्रीय कार्यशाला ने क्षेत्र में विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। जीईएम, भारतीय रेलवे, विश्व बैंक के प्रख्यात वक्ताओं और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के उपयोगकर्ताओं ने अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए। इसके अलावा, कार्यशाला ने उन संस्थाओं को मान्यता दी और सम्मानित किया जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ई-प्रोक्वोरमेंट प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। उन संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने असाधारण परिणाम प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनिक खरीद की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण दिया है।

- सूचना विज्ञान न्यूजडेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने नागरिकों को यातायात चालान के विवाद में मदद करने के लिए डिजिटल अदालतें लॉन्च की

डॉ न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायाधीश और सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष, श्री न्यायमूर्ति राजीव शकधर की उपस्थिति में 28 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय हेतु ई-कारावास प्लेटफॉर्म पर विवादित ट्रैफिक चालान के लिए डिजिटल अदालतें और 'जमानत आदेश साझा करने वाला मॉड्यूल का शुभारंभ किया।

इस पहल की सराहना करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इससे उन नागरिकों को निर्बाध पहुंच मिलेगी जो उन्हें जारी किए गए चालान का मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल शुरू करने का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि न केवल जेलों को आदेश संप्रेषित किए जाएं बल्कि उन आदेशों का अनुपालन भी किया जाए।

दिल्ली में कड़कड़ूमा कोर्ट के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों में विवादित ट्रैफिक चालान के लिए दो डिजिटल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। ये डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट के माध्यम से विवादित चालानों के फैसले को संभालेंगे, वस्तुतः कार्यवाही करेंगे, जिसमें साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, दलीलें सुनना और दिल्ली उच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग नियम, 2021 के साथ-साथ न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम, 2021 का पालन करना शामिल है। उल्लंघनकर्ता अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हो सकते हैं, और दोषी पाए जाने पर वे वेब पोर्टल <https://pay.ecourts.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना भर सकते हैं। योजना दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में एक डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट स्थापित करने की है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन करने के लिए, एक 'जमानत आदेश साझाकरण मॉड्यूल' की भी कल्पना की गई है। मॉड्यूल को एनआईसी-आईसीजेएस डिवीजन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिल्ली जेल के परामर्श से विकसित किया गया था। यह मॉड्यूल उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के लिए देश भर की



भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए ई-कारावास प्लेटफॉर्म पर विवादित ट्रैफिक चालान के लिए डिजिटल कोर्ट और 'जमानत आदेश साझा करने वाले मॉड्यूल' का शुभारंभ किया।

किसी भी जेल में कैदियों और विचाराधीन कैदियों को प्रामाणिकता के साथ हस्ताक्षरित जमानत आदेशों को डिजिटल रूप से साझा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, ई-कारावास प्रणाली उन मामलों की एक सूची तैयार करेगी जहां जमानत दिए जाने के बावजूद कैदियों को रिहा नहीं किया गया है। इस तंत्र का उद्देश्य कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और उचित कार्रवाई करने में कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहायता करना है।

दिल्ली उच्च न्यायालय पहले से ही ई-फाइलिंग, ई-निरीक्षण, ई-आरटीआई आदि जैसी आईसीटी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। डिजिटल ट्रैफिक अदालतों और जमानत आदेश साझाकरण मॉड्यूल की शुरूआत: ई-कारावास न्यायपालिका के भीतर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार करेगा, जिससे नागरिकों के लिए उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच बढ़ेगी।

- सूचना विज्ञान न्यूजडेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

माननीय मुख्यमंत्री असम ने कैबिनेट कार्यवाही को डिजिटल बनाने के लिए ई-मंत्रीसभा का शुभारंभ किया

31 मई 2023 को, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस कैबिनेट बैठक आयोजित करके आधिकारिक तौर पर ई-मंत्रीसभा एप्लिकेशन लॉन्च किया।

ई-मंत्रीसभा एप्लिकेशन ने कैबिनेट बैठक से जुड़ी सभी गतिविधियों को स्वचालित कर दिया है, जिससे वेब पोर्टल पर विभागों द्वारा ज्ञापन तैयार करने से लेकर अनुमोदन प्राप्त करने और बैठक के एजेंडे में शामिल करने के लिए कैबिनेट सेल को अनुमोदित ज्ञापन प्रस्तुत करने तक की पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कैबिनेट बैठकों के शेड्यूल, बैठक नोटिस और एजेंडा तैयार करने में सक्षम बनाता है, और बैठक के समापन तक वास्तविक समय में एजेंडे में अतिरिक्त आइटम जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है।

बैठक के एजेंडे तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रियों को दो प्रकार के एप्लिकेशन उपलब्ध कराए जाते हैं :

1. विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लिकेशन: कैबिनेट मीटिंग रूम में उपलब्ध डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया गया।
2. एंड्रॉइड एप्लिकेशन: प्रत्येक मंत्री के एंड्रॉइड टैबलेट पर इंस्टॉल किया गया।

दोनों एप्लिकेशन बैठक के एजेंडा बिंदुओं को देखने के साधन के रूप में कार्य करते हैं, जहां सभी ज्ञापन और अनुलग्नक दस्तावेज प्रदर्शित होते हैं। यह प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दक्षता और पहुंच को बढ़ावा देता है।

ई-मंत्रीसभा एप्लिकेशन न केवल विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों के साथ कैबिनेट निर्णयों को रिकॉर्ड करने और साझा करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य



माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा की अध्यक्षता में ई-मंत्रीसभा एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए एक डिजिटल कैबिनेट बैठक

सचिव कार्यालय के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें कैबिनेट निर्णयों से संबंधित कार्य की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। फाइलों की भौतिक आवाजाही को समाप्त करके और वास्तविक समय की जानकारी साझा करने को सक्षम करके, ई-मंत्रीसभा असम का उद्देश्य कैबिनेट बैठकों के दौरान कागज के उपयोग को कम करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। ई-मंत्रीसभा को अपना डिजिटलीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रौद्योगिकी को अपनाकर और कागज रहित प्रणाली में परिवर्तन करके, अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की जाएगी, जो शासन को बढ़ाने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लाभों को प्रदर्शित करेगा।

- कविता बरकाकोटी, असम

माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए साथी की शुरुआत की

डि डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज प्रमाणीकरण ट्रेसिबिलिटी और समग्र सूची (SATHI) पोर्टल लॉन्च किया है। एनआईसी द्वारा विकसित यह अत्याधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म पूरे भारत में किसानों के बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी और इन्वेंट्री प्रबंधन सेवाओं तक पहुंचने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है।

साथी एक व्यापक समाधान का प्रतीक है जो कई पीढ़ियों तक फैले संपूर्ण बीज जीवन चक्र को शामिल करता है। अपनी स्वचालित सुविधाओं के माध्यम से, यह अग्रणी पोर्टल उत्पादन और प्रमाणीकरण से लेकर लाइसेंसिंग, इन्वेंट्री नियंत्रण और प्रमाणित डीलरों द्वारा बीज उत्पादकों को बिक्री तक बीज आपूर्ति श्रृंखला के निर्बाध प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बीजों की पूर्ण पारदर्शिता और पता लगाने की गारंटी देता है, जिससे किसानों को अपने कृषि कार्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है।

साथी पोर्टल के केंद्र में भारत मैप इंटरफेस पर आधारित उल्लेखनीय जीआईएस रिपोर्टें हैं। यह अत्याधुनिक कार्यक्षमता किसानों को उनकी बीज-संबंधित गतिविधियों में भौगोलिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, पोर्टल एक वॉलेट सेवा प्रदान करता है, जो किसानों को बीज खरीद और बिक्री से जुड़े अपने वित्तीय लेनदेन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

साथी पोर्टल का एक प्रमुख आकर्षण इसका ऑफलाइन-अनुकूल और डिवाइस-एग्नोस्टिक मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे डिजिटल विभाजन को पाटने और देश के सभी कोनों में किसानों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसान इंटरनेट कनेक्टिविटी या अपने पास मौजूद डिवाइस के प्रकार के आधार पर सीमाओं के बिना पोर्टल की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाओं तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हो सकता है। बीज उद्योग में गुणवत्ता आश्वासन सर्वोपरि है, और साथी पोर्टल अपने एकीकृत गुणवत्ता निरीक्षण मॉड्यूल के साथ इसे ध्यान में रखता है। यह सुविधा किसानों को निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से गुणवत्ता जांच करने का अधिकार देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल सर्वोत्तम बीज वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा, पोर्टल संसाधित सत्यापन डेटा के आधार पर सिस्टम-जनरेटेड नमूना पर्चियां तैयार करता है, जिससे व्यापक विश्लेषण के लिए बीज



माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल भारत के किसानों को समर्पित किया

परीक्षण प्रयोगशालाओं को नमूने अग्रेषित करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।

साथी पोर्टल द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ बीज पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विभिन्न हितधारकों को सेवा प्रदान करती हैं। बीज उत्पादक एजेंसियां विभिन्न राज्यों में संबंधित बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों के तहत आसानी से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं या अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकती हैं। इसी प्रकार, बीज प्रसंस्करण संयंत्र आसानी से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं या अपनी मौजूदा स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं। बीज डीलरशिप लाइसेंस प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाले व्यवसाय आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं या अपनी प्रगति पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा, किसान गुणवत्ता निरीक्षकों द्वारा अपलोड की गई क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के साथ-साथ बीजों के मूल और गंतव्य सहित महत्वपूर्ण विवरणों का पता लगा सकते हैं।

SATHI पोर्टल के लॉन्च के साथ, भारतीय कृषि क्षेत्र बीज-संबंधित प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और सुव्यवस्थित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग देख रहा है। यह पहल किसानों को सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच, बढ़ी हुई पारदर्शिता और बीज आपूर्ति श्रृंखला के भीतर बढ़ी हुई दक्षता के साथ सशक्त बनाने का वादा करती है।

- सूचना विज्ञान न्यूज़डेस्क, एनआईसी-मुख्यालय

डिजिटल दान और दर्शन प्रणाली के माध्यम से तीर्थयात्रा के अनुभव को मिली सुगमता

आ ध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड ने श्रद्धालुओं के लिए तीर्थयात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धेय चार धाम यात्रा के लिए एक पीओएस-आधारित दान संग्रह प्रणाली और एक प्रोटोकॉल दर्शन प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। इन पहलों का उद्देश्य दान संग्रह की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना और तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज दर्शन अनुभव प्रदान करना है।

7 मई 2023 को लॉन्च की गई, पीओएस-आधारित दान संग्रह प्रणाली, राज्य सरकार को 11,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑफलाइन मोड में दान एकत्र करने की अनुमति देती है। यह प्रणाली ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में एक विश्वसनीय और कुशल दान संग्रह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। यह धन संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा।

प्रोटोकॉल दर्शन प्रणाली चार धाम यात्रा के लिए शुरू किया गया एक और महत्वपूर्ण विकास है। इस प्रणाली के तहत, तीर्थयात्री पवित्र मंदिरों में सुप्रवाही और सुव्यवस्थित दर्शन प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे। इसका उद्देश्य लंबे समय तक प्रतीक्षा समय को समाप्त करना और भक्तों के लिए एक कुशल और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है।

इन प्रणालियों के कार्यान्वयन के साथ, तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के प्रतिष्ठित मंदिरों की सहज और अधिक व्यवस्थित यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं।

- राजीव जोशी, उत्तराखंड



उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री पुष्कर सिंह धामी, चार धाम यात्रा के लिए पीओएस-आधारित दान संग्रह प्रणाली और प्रोटोकॉल दर्शन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए

देशभर में ई-शासन गतिविधियों के बारे में नवीनतम व अद्यतन समाचारों व सूचना के लिये News पर जाये <https://informatics.nic.in/news>